(b) if so, whether it is also a fact that too much emphasis has been placed on acquaculrture by MPEDA; and

(c) if so, whether Government propose to conduct a review of this policy

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) No, Sir

(e) and (c) Do not arise.

कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों की छंटनी

817. श्री शारदा महन्ती :
श्री सोमपाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से कॉफी बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की छंटनी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ;

(ग) इस समय कॉफी बोर्ड के आय और व्यय का ब्यौरा क्या है और इन बचत कार्यक्रमों को करने के पश्चात् इसके व्यय में कितनी कमी आने की संभावना है ; और

(घ) कॉफी बोर्ड के कार्यकरण पर अधिकारियों और कर्मचारियों की छंटनी से कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करने हेतु क्या पूर्व सावधानियां बरती जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। कॉफी बोर्ड ने अपने विपणन क्रियाकलापों में कमी होने के परिणामस्वरूप बेशी श्रम शक्ति को कम करने के लिए तथा विपणन की लागत को कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं ।

(ख) वर्ष 1992-93 में 30% घरेलू बिक्री कोटा प्रदान किए जाने तथा वर्ष 1993-94 मौसम से 50% मुक्त बिक्री कोटा दिये जाने के फलस्वरूप कॉफी बोर्ड के विपणन क्रियाकलाप में काफी कमी आई है, जिसके फलस्वरूप श्रम शक्ति बेशी हुई है और इस प्रकार बोर्ड के पास एकत्र की गई जो उपलब्ध कॉफी थी उसका विपणन अधिक खर्चीला हो गया । कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों के एक हिस्से के लिए अनुमोदित की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जल्दी ही लागू किए जाने की संभावना है ।

(ग) कॉफी बोर्ड की अपनी कोई निजी आय नहीं है क्योंकि उपजकर्ताओं द्वारा संग्रहीत कॉफी के विपणन से प्राप्त आय को विपणन लागत तथा प्रशासनिक व्यय काटने के पश्चात् उनके बीच वितरित कर दिया जाता है । स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लागू होने पर कॉफी की विपणन-लागत में पर्याप्त कमी होने की संभावना है ।

(घ) श्रम शक्ति में उक्त कटौती केवल कॉफी बोर्ड के विपणन निदेशालय में ही करने का विचार है, जहां पता चला है कि कम हुए क्रिया-कलापों की वजह से श्रम शक्ति बेशी हो गई है । इसलिये बोर्ड के अन्य क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Export of Milk powder

618. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Mlinister of COMMERCE be pleased to state:

(a.) whether it is a. fact that export of milk powder is still under control by Government;

(b) if so, what are the obstacles on the way of allowing export of milk! powder and conditionalitiee laid down for it;

(c) what are the efforts made by Government to increase the produc-

tion of milk.powder in the country; and

(d) what are the results thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) With the objective of promoting export® of milk powder, its export has been decanalised with effect from 29.9.1994. Exports arc now being allowed against quantitative ceilings which are placed at the disposal of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. Exports are permitted subject only to quality specifications and compulsory preshipment inspection by designated agencies.

(e) and (d) The Government has already delicensed the milk products industry under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 sub ject to locational parameters. Due to the liberalised policy of the Govern ment, the production of milk powders including infant milk foods has incre ased from 1,65,000 tonnes in the year 1992 to 1,85,000 tonnes in the year 1993.

Open licencing of paddy shelling

819. SHKI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of COMMERCE, be pleased to state 1

(a) whether under the liberalization policy of Government open licencing of shelling of paddy *rum* been allowed'

(b) if so, since when; and

(c) if not, the reasons therefnr?

THE MINISTER OF COMMERCE SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise-

(c) All rice millers in the country are required to obtain a permt under Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958andRice-Milling. Industry '(Regulation & Licensing) Rules, 1959 before commencing milling perations.

Private and state sectors o set up EPZs

520. SHRI K. M. KHAN:
SHRI IQBAL SINGH:

Will the Minister of COMMERCE be pleesed to state:

(a) whether the private and State sectors have been permitted to *set up* export procesing zones;

(b) if so, the details thereof with objectives;

(c) whether prior to this liberalisation some Export "processing zones were *in* existence;

(d) if so, the details thereof with their functions;

(e) the extent by which EPZ are likely to the help in the development of infrastructural facilities for industrial development and export; *end*

(f) if so, the details thereof and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes. Sir.

(b) to (f) The Government has recently decided to permit establishment of Export Processing Zones (EPZs) by the private joint sector or Stat? Governments with a view to involving the private and State sectors in the provision of infrastructural facilities for industrial development and exports. Policy, procedures and benefits in respect of units in EPZs would nlso apply in the case of EPZ", developed by the private [joint sector or State Governments. EPZ promoters would have to fulfill the "prescribed requirements of security as well as relevant customs lawn and procedures, beer the custom banding charges, comply with local industrial, labour or